

>

Title: Regarding alleged misuse of MPLAD and Rural Development funds by the State Governments and its officers.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल):** सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अति लोक महत्त्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मैं पूर्व में भी यह मामला सदन में उठा चुका हूँ और पुनः उठाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, सांसद निधि और भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो भी परियोजनाएँ हैं, उन पर बंदरबांट हो रहा है। यही नहीं, जिले में जब डीआरडीए की बैठक होती है, तब मनमाने ढंग से वहाँ जन प्रतिनिधि इंदिरा आवास का बंदरबांट करते हैं। इसी तरह से हैंडपम्पस का भी बंदरबांट होता है। क्षेत्र के सांसद को पूछा नहीं जाता और न उनसे कोई योजना ली जा रही है। यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांवों का ही विकास हो रहा है, अन्य गांवों को छोड़ा जा रहा है। अगर हम इसकी शिकायत जिला अधिकारी या सीडीओ से करते हैं, तो पहले तो वे हमारी बात सुनते ही नहीं और जब सुनते हैं तो कहते हैं कि हमें पहले अम्बेडकर गांवों को देखना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सांसद निधि की बात है, इसे या तो बढ़ाया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इतनी कम राशि में क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सांसदों पर इसका कुपूवार करके साजिश होती है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि सांसद निधि और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो निगरानी समितियाँ मंत्री जी ने गठित की हैं, उनमें अध्यक्ष को सुना नहीं जाता। जब हम डीआरडीए में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी बंदरबांट हो रही है। इसलिए भारत सरकार इस पर ध्यान देकर समुचित कार्यवाही करे और एम.पी.ज़., एम.एल.ए.ज़ और एम.एल.सी.ज़. सबकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करे।